



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

पं: 16]

नई दिल्ली, बृद्धपाल, मई 8, 1991/वैशाख 18, 1913

No. 16] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 1991/VAISAKHA 18, 1913

इसे भाग में निम्न पृष्ठ सेवा दी जाती है तिससे कि वह असाधारण के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पंजाब एण्ड सिंघ बैंक

(कार्मिक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 1991

स. 1 पीएसबो/स्टाफ/आएसआर/1991 —बैंकिंग कार्पोरेशन (उपक्रमों का अंजीन और अंतर्राष्ट्रीय) विनियम, 1980 (1980 का 40) के खण्ड 19 में प्रदृश्य अधिकारों को प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह लेकर केन्द्रीय सरकार को पूर्व स्वीकृति से पंजाब एण्ड सिंघ बैंक के नियन्त्रक मैट्टल के संदर्भ एकदारों पंजाब एण्ड सिंघ बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम-1982 में संशोधन हैं तु निम्न विनियम बनाते हैं।

संक्षिप्त शार्पिक एवं प्रारम्भ:—

(1) इन विनियमों को पंजाब एण्ड सिंघ बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) यह विनियम सरकारी बैंकों में प्रकाशित की तिथि से लागू होगे।

विनियम-21 निम्नानुसार संशोधित है —

(21) दिनांक 1-11-1987 को तथा उसके बाद से महगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :—

(1) महगाई भत्ता अविल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकाक (सामान्य) आधार 1960-100 की तिमाही औसत में 600 श्रमों के ऊपर 4 श्रेणी की प्रत्येक बांड अथवा गिरावट के हिसाब से देय होगी।

(2) महगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा —

(1) रु. 2500/- तक वैतन का 0.67%, और

(2) रु. 2500/- से ऊपर परतु रु. 4000/- तक वैतन का 0.55%, और

(3) रु. 4000/- से ऊपर परतु रु. 4260/- तक वैतन का 0.33%, और

(4) रु. 4260/- से ऊपर वैतन का 0.17%

विनियम-22 (2) और विनियम 22(3) के सम्बन्धीकरण । (1) और सम्बन्धीकरण 2 निम्नानुसार संशोधित है :—

22(2) 1-1-1990 को और उसके बाद में, यदि किसी अधिकारी जो वैक द्वारा नकान नहीं दिया गया है, तो वह निम्नलिखित वरों पर मकान किराया भता पाने का पात्र होगा :—

संग्र-1	संग्र-2
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर हीने पर	देय मकान किराया भता
(1) मरकान के मार्गनिर्देश के अनु-सार समय-समय पर विनियम	वेतन का 14% परमु अधिकतम 450/- रु. प्र. मा.
प्रमूख "ए" शर्त के नगर नथा मध्यम "ए" के परियोजना क्षेत्र	
(2) क्षेत्र-1 में व्यापक स्थान तथा समृद्धि के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% परमु अधिकतम रु. "बी" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र 375/- प्र. मा.
(3) क्षेत्र 2 तथा (उपक्षेत्र) 1 तथा वेतन का 10% परमु अधिकतम (2) के अन्तर्गत न शाने वांग राज्यों नथा सर्व ग्रामीण क्षेत्रों की राजधानियां	रु. 325/- प्र. मा.,
(4) क्षेत्र-3	वेतन का 8% परमु अधिकतम रु. 300/- प्र. मा.

परंतु यदि कोई अधिकारी किराए की अधीक्षा प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भता, जिस वेतनमात्र में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 6 प्रतिशत से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया अथवा सम्बन्ध-2 से उल्लिखित वरों पर, जो भी कम हो अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भता का अधिक से अधिक 175% होगा

सम्बन्धीकरण :—

(1) (ब) विनांक 1-4-1990 को या उसके बाद में यदि नियास स्थान वैक द्वारा किराए पर दिया गया है तो वैक द्वारा देय मंदिवागत किराया अथवा उपर "क" में दर्शाई गई प्रति के अनुसार आंका गया किराया, जो भी कम हो ।

(2) इस विनियम और विनियम-23 में क्षेत्र-1, क्षेत्र-2 तथा क्षेत्र-3 का अर्थ निम्नानुसार होगा :—

क्षेत्र-1 — 12 लाख से अधिक जन संख्या वाले स्थान ।

क्षेत्र-2 — क्षेत्र-1 में न जाने वाले ऐसे सभी शहर जिनकी जन-संख्या 1 लाख और उसमें प्रतिक हो ।

क्षेत्र-3 — क्षेत्र-1 और क्षेत्र-2 में न जाने वाले अन्य सभी स्थान ।

विनियम-24 निम्नानुसार संशोधित है :—

विनियम 24

(1) अधिकारी भाने और भरने परिवार के लिए किए गए वास्तविक विकिस्ता व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात् :—

(क) विकिस्ता व्यय :—

1-1-90 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए विकिस्ता व्यय की प्रतिपूर्ति भी वे संभन्न-1 में विनियमित वेतन सीमा तथा

सम्बन्ध-2 में विनियमित प्रतिपूर्ति भीमा के अध्यवैत की जाएगी। इसके लिए अधिकारी की अपनी और से ही प्रमाणपत्र द्वारा होगा कि उसने यह व्यय किया है और वाका की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च ना विवरण देना होगा ।

सारणी

वेतन सीमा	वापिक प्रतिपूर्ति भीमा
1	2
रु. 2100/- से . 3060/-	रु. 750/-
रु. 3061/- प्र. मा. और अधिक	रु. 1000/-

टिप्पणी : उपनोग में न आई विकिस्ता यहांयता राशि की अधिकारी संभित कर सकता है परंतु संवित राशि किसी भी समर्थ उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुणे से अधिक नहीं होगी।

सम्बन्धीकरण :—

इस विनियम के प्रयोजन के लिए, अधिकारी के परिवार में उसका पति/ उसकी पत्नी, पूर्णतः सामित्र संवान और पूर्णतः आश्रित भाता-पिता ही शामिल होंगे ।

(ब) अस्पताल में भर्ती छर्च :—

(1) विनांक 1-4-1989 को और उसके बाद से ऐसे सभी मामलों में जिसमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 90% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक के अधीक्षा की प्रतिपूर्ति भी जाएगी। किए गए अधीक्षा की प्रतिपूर्ति विल, बालबाल आधार के आधार पर सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित भीमा के अन्तर्गत की जाएगी।

(2) अधिकारियों द्वारा उनके परिवार के सदस्यों से, यथास्थिति, वह उपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नागर पालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल (अर्थात् किसी यात्रा, घरमर्थ संस्थान या व्यायामिक मिशन के प्रबंध के अधीक्षा वाले वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किसी अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निवास योग्य द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति भार विषय अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि तक सीमित रहेगी ।

(3) 1-4-1989 को और उसके बाद से भाग्यताप्राप्त अस्पताल के अधिकारियों और वैक के विकिस्ता अधिकारी द्वारा वह पर हालाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के विकिस्ता व्यवहारों की भी अस्पताल में भर्ती अधीक्षा मात्रा जाएगा और उसमें संवित विकिस्ता व्यवहारों की अधिकारी के मामले में 90% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60% तक प्रतिपूर्ति भी जाएगी ।

कैंसर, सपेदिक, पक्षाधात, हृदय रोग, द्रव्यमर, जेवर, लूरिसी, विषधीरिया, कुण्डरोग, गुर्व की व्यावहारी ।

विनियम 33(4) निम्नानुसार संशोधित है :—

विनियम 33(4) 1-1-1990 को और उसके बाद से, जब तक कि आवेदित छही नामंजूर या कर दी गई हो, विसेप्राधिकार छही, अधिक से अधिक 240 विनों तक संवित भी

दिनांक 1-1-1987 से विनियम 41(4)(च) निम्नानुसार भेंगोधित है :—

(च) सभी निरीक्षण भविकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण शृंखला पर विराम के प्रतिदिन के लिए रु. 10/- का अनुदर्शक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है।

एन. एस. पुराण,
उप महाप्रबन्धक (कानूनी)

PUNJAB & SIND BANK

(Personnel Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 1991

No. PSB/Staff/OSR/1991.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Punjab & Sind Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Punjab & Sind Bank (Officers) Service Regulations 1982.

Short title and Commencement:

- These regulations may be called the Punjab & Sind Bank (Officers) Service (Amendment) Regulations, 1991.
- They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

Regulation 21 stands amended as under :

REG. 21—On and from 1-1-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

- Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) base 1960 = 100.
- Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—
 - 0.67% of 'Pay' upto Rs. 2500/- plus,
 - 0.55% of 'Pay' above Rs. 2500 to Rs. 4000 plus,
 - 0.33% of 'Pay' above Rs. 4000 to Rs. 4260 plus,
 - 0.17% of 'Pay' above Rs. 4260.

Regulation 22 (2) and Explanation 1(b) and Explanation (2) under Regulation 22 (3) stands amended as under :—

REG. On and from 1-1-1990, where an officer is not provided 22(2) any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Column-I

Where the place of work is in
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Govt. & Project Area Centres in Group 'A'

(ii) Other places in Area-I and Project Area Centres in Group

Column-II

HRA Payable shall be 14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450 p.m.

12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375

- Area-II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) Above
- Area-III

10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325 p.m.

8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300 p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay, in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise, whichever is lower.

Explanation:

With effect from 1-4-1990.

1(b) where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area-I, Area-II, and Area-III shall mean as under :—

Area-I —Places with a population of more than 22 lakhs

Area-II —All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more.

Area-III —All places not included in Area I and Area II.

Regulation 24 stands amended as under :

Reg. 24 (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses:

On and from 1-1-1990 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in Column I of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in Column 2 thereof:

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.a.	
	1	2
Rs. 2100 to Rs. 3060 p.m.		Rs. 750
Rs. 3061 p.m. and above		Rs. 1000

Note: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

Explanation:

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses:

(i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90% in the case of an

officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc. of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the government.

- (ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.
- (iii) On and from 1-4-1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domi-

ciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90% in case of an officer and 60% in the case of his family members: —

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumor, Small Pox, Pleurosy, Diphteria, Leprosy, Kidney Ailment.

Regulations 33 (4) stands amended as under:

REG. 33(4) On and from 1-1-1990 privilege leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused.

Regulation 41 (4) (f) stands amended w.e.f. 1-1-1987 as under:

(f) A supplementary Diem Allowance of Rs. 10/- per day of halt outside head quarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

N.S. GUJRAL, Dy. Gen. Manager (Personnel)